भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3171

18 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

एससीएम में बीआईएम प्रौद्योगिकी का उपयोग

†3171. श्री सुनील कुमारः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पूरे देश में बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग (बीआईएम) तकनीक के उपयोग वाली स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का बिहार सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजनाओं के नाम क्या हैं, उनके स्थान क्या हैं और उनकी लागत कितनी है;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है और बीआईएम प्रौद्योगिकी के उपयोग से प्राप्त लाभ क्या हैं;

(ग) इन परियोजनाओं में बीआईएम प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन में शामिल अभियंताओं और कंपनियों के नाम क्या हैं;

(घ) इन परियोजनाओं की दक्षता और उत्पादकता और निर्माण के समय और लागत में कमी (यदि कोई हो) पर बीआईएम तकनीक का प्रभाव क्या है; और

(ङ) सरकार की पूरे देश में राज्य-वार अन्य स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में बीआईएम प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने को बढ़ावा दिए जाने की क्या योजना है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ) स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य पूरे शहर का विकास करना नहीं था, बल्कि रेट्रोफिटिंग, पुनर्विकास, ग्रीनफील्ड विकास और एक अखिल-शहरी पहल के माध्यम से क्षेत्र-आधारित विकास दृष्टिकोण अपनाना था, जिसमें स्मार्ट समाधानों को शहर के बड़े हिस्सों में लागू किया जाता है, ताकि एक अनुकरणीय मॉडल तैयार किया जा सके। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आने वाले शहरों का विकास विभिन्न क्षेत्रों, जैसे स्मार्ट मोबिलिटी, जल, स्वच्छता,

साफ-सफाई (वाश), स्मार्ट गवर्नेंस, स्मार्ट ऊर्जा, पर्यावरण आदि में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त स्मार्ट सिटी प्रस्तावों (एससीपी) के आधार पर किया जा रहा है, जिन्हें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एचपीएससी) द्वारा अनुमोदित किया गया है।

स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) का शहरी स्तर पर कार्यान्वयन योजना बनाने, मूल्यांकन करने, परियोजनाओं को अनुमोदित करने, निधि जारी करने, खरीद, प्रबंधन, संचालन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए गठित विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी) द्वारा किया गया है। ये एसपीवी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के संयुक्त स्वामित्व में हैं और इनमें दोनों की समान हिस्सेदारी है।

चूंकि स्मार्ट सिटी मिशन एक शहर स्तरीय परियोजना है, इसलिए जानकारी केवल शहर स्तर पर ही रखी जाती है।

*****